

# नवभारत टाइम्स

नई दिल्ली, 14 नवम्बर 2000

बहस

## चीनी माल पर रोक लगे

**हमारा मत है कि भारत में आ रहे चीनी उत्पादों पर तत्काल रोक लगाई जाए क्योंकि हमारे छोटे उद्योग तबाह होने के कगार पर हैं।**

**ची**न से इन दिनों बड़े पमाने पर कपड़े, पेंसिल बैटरियों, खिलौनों, साइकिलों तथा टायरों आदि का आयात हो रहा है। भारत में बिकने वाली इन चीजों में से ज्यादातर नेपाल तथा अन्य पड़ोसी राष्ट्रों से तस्करी के जरिये लायी जा रही हैं। इन चीजों की क्वालिटी भले ही घटिया हो लेकिन ये इतनी सस्ती हैं कि उपभोक्ता इन्हें खरीदने का लोभ संवरण नहीं कर पाते। अगर सात रुपये की चीज महज पचास पैसे में मिले तो जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे उसे ही खरीदेगा। हैयानी की बात यह है कि इतने कम दामों में ये चीजें भारत में कैसे बिक रही हैं जबकि इनकी लागत निश्चित रूप से कई गुना ज्यादा होगी। इसका मतलब साफ है कि ये चीजें यहां डम्प की जा रही हैं। इनके प्रभाव से हमारे उद्योगों को भारी धक्का पहुंचने लगा है। बहुत से छोटे उद्योगों के तो बंद होने की नौबत आने लगी है। ऐसा लगता है कि एक सोची समझी नीति के तहत इन्हें भारत के बाजारों में धकेला जा रहा है। इससे हमारी उत्पादक इकाइयां अनुत्पादक हो जाएंगी और वे आयात पर निर्भर हो जाएंगी। भारतीय छोटे उद्योग इस समय वैसे ही एक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, मांग में कमी के कारण उनके लिए अपने को बचाए रखना कठिन हो गया है। चीनी वस्तुओं की इस बरसात से उनके सामने बंदी के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। हमारा मानना है कि इस तरह के असंतुलित आयात या तस्करी को तत्काल रोका जाए।

**प्रतिसम्पादकीय/ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के निदेशक प्रो. जे डी अग्रवाल** का कहना है कि सवाल हमारे उद्योगों के चौपट होने का नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का है।

**ची**नी सामान का इतने बड़े पैमाने पर भारत आना मन में संशय पैदा करता है। यह निश्चित रूप से योजनाबद्ध ढंग से हमारे उद्योगों को तबाह करने के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। सरकार को इस बारे में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। न केवल सीमा के उस पार से आने वाले सामान की धरपकड़ की जानी चाहिए, बल्कि उसे रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी अभियान चलाना चाहिए। यह सामान नेपाल के रास्ते भारत के साथ एक संधि के तहत लाया जा रहा है। इस बारे में भी सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और अगर भारत-नेपाल व्यापार संधि में कोई छिद्र है तो उसे भी बंद करना चाहिए।